

During this period, two foreign banks, namely, Grindlays Bank and Bank of America which were already operating in India, were permitted to open an additional branch at Calcutta in November, 1969 and at Bombay in September, 1977 respectively. Therefore, we have these five plus two *i.e.*, seven new branches of foreign banks operating here after nationalisation. The hon. Member would appreciate that it is not a big number when we have more than 38,000 branches of the Scheduled commercial banks.

Regarding the first part of his question about the non-supply of figures, if you see the text of the question you will appreciate that such a supplementary would not arise out of the question. But we do not have any hesitation in giving the figures. As has been told by my colleague, it will require some time to collect the information and we will give it to the hon. Member.

Official Delegations sent abroad on Purchase Missions

*22. SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that official delegations on purchase missions are frequently sent to various countries for buying import requirements;

(b) if so, the number of such delegations sent and the money spent thereon during the last year;

(c) the reasons for not meeting import needs from the annual international trade exhibitions in the country;

(d) whether it is also a fact that many developed nations ignore Indian trade exhibitions due to the Government's unrealistic purchasing policy; and

(e) the details of steps proposed to be taken to ensure participation of main exporters to India in international trade fairs and making the purchases in these fairs?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): (a) to (e): A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b). No, Sir. No official delegation on Purchase Mission from the Ministry of Commerce was sent to any country during the last one year.

(c) Essential imports for the economy are facilitated through the import policy which is announced annually. International trade exhibitions are generally used for projecting the image of the exporting country and for introducing merchandise. They are generally not primarily meant for spot purchases, even though contracts are entered into on the basis of samples at such trade fairs. Keeping in view the composition and volume of our import requirements, there are severe limitations to the use of annual international trade exhibitions held in the country for meeting our import needs. It is not correct to say that many countries ignored the exhibitions due to Government's unrealistic purchasing policy.

(d) As many as 39 countries participated in the India International Trade Fair 1981, apart from a number of commercial enterprises from all over the world. These countries included developed countries also.

(e) The Trade Fair Authority of India who are charged with the responsibility of organising international trade fairs in India and abroad give wide publicity to the fairs to attract participation by other Governments and by private companies. Preparations including advance publicity are undertaken for eliciting maximum participation.

Certain special facilities have been offered to foreign exporters by introduction of a 'fair quota' for sale on the spot.

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न की स्पष्ट मंशा थी कि अपनी

आयात की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये क्या यह सही है कि भारत-सरकार की ओर से, प्राइवेट कंपनीज की ओर से, विभिन्न मंत्रालयों की ओर से, पब्लिक सेक्टर्स की ओर से, गवर्नमेंट एजेंसीज को ओर से खरीद करने के लिये प्रतिनिधिमंडल देश के बाहर जाते हैं, जिन पर काफी खर्चा होता है। इसका उत्तर मंत्रालय द्वारा दिया गया है कि कामर्स मिनिस्ट्री से कोई डेलीगेशन नहीं भेजा गया। मैं समझता हूँ कि इस तरह के उत्तर से प्रश्न की गंभीरता को कम किया गया है। यह स्पष्ट है कि आज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जो प्रतिनिधिमंडल परचेजेज के लिये बाहर जाते हैं, उनके उपर कई तरह के आरोप हैं, मिस-यूज के, टी० ए० डी० ए० अनाप-शनाप कमाने के। जब ट्रेड फेयर अथारिटी आफ इंडिया प्रति वर्ष ट्रेड फेयर अरेंज करती है तो क्यों नहीं भारत सरकार यह अनिवार्य करती कि अपनी आयात की पूर्ति के लिये जो भी खरीदियां होंगी, वे ट्रेड फेयर से ही होंगी। इसके संबंध में क्या यह सही है कि कई विकसित देश, जिनमें विशेषकर पश्चिमी जर्मनी है, उसने यह अनिवार्य किया हुआ है कि वे देश परचेजेज ट्रेड फेयर के माध्यम से ही करेंगे; जो देश ट्रेड फेयर में शामिल होंगे, उन्हीं से खरीददारी की जायेगी, वरना नहीं की जायेगी। क्या भारत-सरकार इसी प्रकार की अनिवार्यता लागू करना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हो गया आपका प्रश्न।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : हमारी इस कमजोरी को देखते हुए यू० के० और यू० एस० ए० हमारे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के अंदर भाग नहीं लेते—क्या यह सही है।

श्री शिवराज बी० पाटिल : हम जो चीजें बाहर से लेते हैं वे किस प्रकार की होती हैं इसको आप देखें कि वे चीजें ट्रेड फेयर अथारिटी के माध्यम से खरीदी जा सकती हैं या नहीं। हमारी जो खरीद होती है उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सीमेंट, आयल, स्टील, इस प्रकार की चीजें हैं और इन्हीं चीजों की ज्यादातर खरीद होती है। 65 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक इनकी खरीद होती है और ट्रेड फेयर में मशीनें, कंज्यूमर गुड्स इस तरह की चीजें वहां पर आती हैं, जिनकी खरीद हम बाहर के देशों से बहुत कम करते हैं। इस तरह की चीजें ट्रेड फेयर अथारिटी के माध्यम से खरीदी भी जा सकती हैं और अथारिटी की एग्जीबीशंस से कुछ पैमाने पर खरीद भी करते हैं, लेकिन दूसरी जो चीजें हैं, जो बल्क होती हैं, ट्रेड फेयर में नहीं आ सकतीं।

जहां तक यू० के० और यू० एस० ए० का सवाल है, यू० के० लोग हमारे पास आते जा रहे हैं, यू० एस० ए० के लोग अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन हमारी खरीद का सवाल इससे संबंधित नहीं है; चीजों की कीमतें कम-ज्यादा होने की बजह से सिर्फ ट्रेड फेयर में आने के बाद ही खरीद की जाये, इससे नुकसान हो सकता है। इन चीजों को ध्यान में रखकर ही जवाब दिया गया है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष जी, जैसा कि उत्तर दिया गया है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खरीद की जाती है, यह बात तो समझ में आती है, लेकिन दूसरी जो 35 परसेंट चीजें खरीदी जाती हैं, क्या उनके लिये बंधन नहीं लगाया जा सकता और इन आरोपों से नहीं बचा जा सकता था? मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सही है कि ट्रेड फेयर अथारिटी आफ इंडिया के चेयरमैन ने भारत सरकार से

मांग की थी कि आने वाले एशियन गेम्स के लिये जो स्पोर्ट्स के लिये सामान खरीदा है... ! उसके लिये पांच प्रमुख देशों को देश के अन्दर आने के लिये बाध्य किया जा सकता है बशर्ते कि बारह करोड़ का सामान हम उन से खरीद करें। क्या यह सही है कि भारत सरकार ने ट्रेड फेयर आथोरिटी के इस आग्रह को, इस निवेदन को ठुकरा दिया है और एशियन गेम्स के लिये जितना सामान खरीदा गया है उस के लिये इंग्लैण्ड देश से बाहर भेजा गया है जिस पर लाखों रुपया खर्च हुआ है और सारी परचेजिज बाहर से की गई है? क्या यह सही है कि सरकार की इस नीति की ट्रेड फेयर आथोरिटी आफ इंडिया के चेयरमैन ने आलोचना भी की है जिस के सामाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुए हैं?

श्री शिवराज बी० पाटिल : इसके संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसके लिये मुझे नोटिस चाहिये। जो सामान की खरीद होती है वह दूसरी मिनिस्ट्री की ओर से होती है। ट्रेड फेयर आथोरिटी ने उन से मालम किया है या नहीं किया है, मुझे मालूम नहीं है।

कपड़े की सप्लाई के लिए राष्ट्रीय कपड़ा निगम को रक्षा मंत्रालय की ओर से टेंडर

* 23. श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रक्षा मंत्रालय ने 30,20,300 मीटर कपड़े की सप्लाई के लिये राष्ट्रीय कपड़ा निगम को 8 दिसम्बर, 1981 को टेंडर संख्या बी/89181/डी० जी० आई०/स्टोर-4-पोलियेस्टर काटन ओलिवग्रीन जारी किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम यह कपड़ा सप्लाई कर रहा है और क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड ने उन्हें तथा पूर्ति और निबटान महानिदेशालय की सिफारिश की है कि यह टेंडर किसी दूसरे मिल को, अन्तरित कर दिया जाये और यदि हां, तो राष्ट्रीय कपड़ा निगम को कितने करोड़ रुपये की हानि होगी और प्राइवेट मिल को कितना लाभ होगा ; और

(ग) राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड द्वारा टेंडर स्वीकार किये जाने के बाद कपड़ा सप्लाई न करने के क्या कारण हैं और क्या तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा सभा पटल पर रखा जाएगा ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): (a) to (c): A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a to (c): Ministry of Defence floated an Open tender enquiry for the supply of 3.02 million metres of Polyester Cloth for Army units. Since it was considered feasible for N.T.C. to supply the entire quantity of cloth, the N.T.C. requested that Ministry to place the order on N.T.C. In two instalments, the entire order was placed on the N.T.C. N.T.C. expected that a sizeable portion of the Order would be produced and supplied by its mills in Bombay. However, since the entire Bombay mill industry has been on strike and because the initial problems in stabilising supplies were more than what was anticipated, N.T.C. has not been able to keep to its supply schedule to the Defence Department. The M/O Defence and N.T.C. have been in continuous dialogue to ensure supply of the contracted quantity from N.T.C. to Defence.

श्री कृष्णचन्द्र पांडे : अध्यक्ष जी, मैंने स्पष्ट प्रश्न किया था लेकिन मंत्री महोदय ने उसका गोल मटोल उत्तर दिया है जिस का